12.14 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

(i) Need for more railway facilities at Tarighat Station (U.P.)

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, पूर्व रेलवे का ताड़ीघाट स्टेशन, गाजीपुर शहर से लगे गंगा के उस पार स्थित है। गंगा पर सड़क के पुल बन जाने से इस स्टेशन का महत्व काफी बढ़ गया है।

बड़ी संख्या में लोग ताड़ी घाट से ब्रान्च लाइन द्वारा दिलदार नगर जाकर रेल-गाड़ियां पकड़ते हैं। ताड़ा घाट से बड़ी संख्या में जाने वाले पैसिंजरों की सुविधाओं के लिए मेरे निम्नलिखित सुझाव हैं :

1. ताड़ीघाट रेलवे स्टेशन का फिर से पुनर्निर्माण कराया जाए, इसमें सभी प्रकार की यात्री सुविधाएं उपलब्ध हों।

2. स्टेशन को गंगा पुल के मार्ग से सीधे जोड़ दिया जाए।

3. ताड़ीघाट से दिलदार नगर तक दिन में तीन बार चलने वाली रेल सेवाओं को पांच बार कर दिया जाए।

4. ताड़ीघाट से लखनऊ के लिए नई रेलगाड़ी चलाई जाए। यदि यह संभव न हो तो मुगलसराय-लखनऊ पैसेंजर को ताड़ीघाट से चलाया जाए।

5. गाजीपुर, आजमगढ़ और बलिया जिलों के बड़ी संख्या में पटना कलकत्ता, आसाम, दिल्ली और पंजाब जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए दिलदार नगर जंकशन स्टेशन पर, आसाम मेल, तूफान मेल तथा मगध एक्सप्रेस का ठहराव किया जाए।

मेरा रेलमंत्री से निवेदन है कि वह व्यापक जनहित की दृष्टि से इस दिशा में शीघ्र कार्यवाही करें।

(ii) Need to instal a High power T.V. transmitter at Gwalior and Low Power Transmitter at Shivpuri and Guna

SHRI MADHAVRAO SCINDIA (Guna) : Gwalior with a population of more than 5½ lakhs is a rapidly growing city. With the establishment of the Mirage-2000 and the fast expanding industrial townships at Banmore and Malanpur, it would become desirable to have a wider TV coverage.

At present, most parts of Gwalior-Chambal Division remain deprived of the benefits of television facilities. Shivpuri with its National Park and idyllic surroundings has been selected by the Government of India as the site for the first tourist village in the country and the project will be compleled by the first half of 1985. Similarly, the construction of Rs. 650/- crore gas-based fertiliser plant in the public sector at Guna would lead to the rapid industrialisation of the area.

Hence I would like to urge upon the Government to instal—

(a) a high power TV transmitter at Gwalior which would be capable of covering Gwalior,

[Shri Madhavrao Scindia]

Morena and Bhind districts of Gwalior-Chambal Division, and

(b) low power transmitters at Shivpuri and Guna.

This would act as a powerful catalytic agent for the socio-economic and cultural growth of the region.

(iii) Need for early Completion of alumina project undertaken by National Aluminium Company Ltd., Orissa.

SHRI CHINTAMANI JENA (Balasore) : Construction work on India's most ambitious projects undertaken by the National Aluminium Company Ltd., the biggest of its kind in the country, was started in the year 1981 and was planned to be completed by the end of the 6th Plan period at a cost of Rs. 1250/- crores, but the progress of work is so slow that it is doubtful if it can be completed by the end of 7th Plan period and as per a spokesman of the Ministry, by the time it will be completed, the cost of the project will be more than double. The State Government of Orissa has provided all the lands required for this project, but the State Government of Orissa and NALCO management have different views of the question of giving preference in employment to local people. Similarly, the 700 tribal families who were uprooted for estabilishment of alumina refinery at Damanjudi have not been rehabilitated yet. In addition to these, there are agitations and labour troubles going on there, for the last one year.

I would request the Union Government to take immediate action to solve these issues, so that this project can be completed soon.

(iv) Need to review the policy of issuing fire arms licences.

श्री बी० डी० सिंह (फूलपुर) : आज देश में गम्भीर अपराध बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। अपराधों के बढ़ने के अनेक कारणों में से एक प्रमुख कारण है—आग्नेय अस्त्रों के लाइसेंस देने की वर्तमान पद्धति। देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश में समाज विरोधी एवं अराजक तत्वों को लाइसेंस प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं है। 1980 के बाद प्राय: सभी ऐसे तत्वों को आग्नेय अस्त्रों के लाइसेंस उपलब्ध हो गए हैं। सम्भ्रान्त नागरिकों को, जिन्हें अपने जीवन एवं सम्पत्ति की रक्षा के लिए वास्तव में लाइसेंस की आवश्यकता है, लाइसेंस प्राप्त करने के लिए दर-दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं और अन्त में निराशा ही हाथ लगती है। इसके अतिरिक्त बड़े पैमाने पर अधिकृत आग्नेय अस्त्रों की आड़ में अनधिकृत आग्नेय अस्त्र प्रयोग किए जा रहे हैं।

इन परिस्थितियों में आज इस बात की नितान्त आवश्यकता हो गई है कि समस्त प्रदत्त लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएं, अथवा उन सभी नागरिकों को लाइसेंस उपलब्ध कर दिए जाएं, जो आग्नेय अस्त्र रखना चाहते हैं।